

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to give houses to slum-dwellers along railway lines in Delhi under Pradhan Mantri Awas Yojana.

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, देश के प्रधान मंत्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश के आज़ादी के 75 साल यानी वर्ष 2022 तक सब को हक का पक्का घर देने का वादा किया है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लगभग सभी राज्यों में घर बनाना प्रारम्भ भी हुआ है। उन्होंने गत वर्ष दिल्ली के लाखों झुग्गीवासियों को, अन-अथोराइज्ड कालोनी का वर्षों पुराना मामला कायदा बनाकर सब को मालिकाना हक देने का काम भी किया है, इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

महोदय, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 48 हजार झुग्गीवासियों को रेल लाइन के पास से हटाने का निर्देश दिया है। हमारी केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप करते ही न्यायालय ने तीन महीने का समय दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि केन्द्र सरकार सब को हक का पक्का घर देने का काम करेगी।

महोदय, मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करता हूँ कि दिल्ली की धरती पर देश के सभी राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर एक साझा नियमावली बनाए और केन्द्र सरकार की जमीन पर बसे हुए सभी परिवारों को एक घर हक का देने का काम वह करे।

महोदय, दशकों पहले, जिनके घर टूटे हैं और सरकार के पास जिनके रिकार्ड हैं, उनको भी घर दिए जाएं। यह माँग मैं आपके माध्यम से करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति :

श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गोपाल शेटी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।